

## जी.आई.एस. पोर्टल मैपिंग क्या है?

### चर्चा में क्यों है ?

केंद्र सरकार द्वारा लैंड एससिस्टिंग इंडस्ट्री (land assisting industry) की तकरीबन आधा मलियन से अधिक भूमि का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया गया है। जी.आई.एस. (Geographic Information System) सक्रम डेटाबेस में 3000 के करीब औद्योगिक पार्कों/समूहों, कृषि/बागवानी फसलों की क्षेत्रवार उपलब्धता तथा खनजि उत्पादन आधारित सूचनाओं का विवरण शामिल किया गया है।

### महत्त्वपूर्ण बढि

- उल्लेखनीय है कि जी.आई.एस. पोर्टल के अंतर्गत जलद ही गोदामों, बजिली-ग्रडि एवं वित्तीय संस्थानों से संबंध जानकारी को शामिल किया जाएगा।
- इसके साथ-साथ इसके अंतर्गत भनिन-भनिन परियोजनाओं हेतु उद्यमियों द्वारा जमा किये गए आवेदनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (industrial infrastructure) संबंधी मांग को भी पूरा किया जाएगा।

### उद्देश्य

- इसका उद्देश्य वर्तमान में देश के औद्योगिक नीति-निर्माण एवं वनिर्माण क्षेत्र में नविश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली सूचना वषिमता (information asymmetry) को समाप्त करना है।

### रोज़गार को बढावा

- वर्तमान में इसके अंतर्गत कुछ वशिष क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएँ संबंध है, जनिमें औद्योगिक पार्कों/समूहों; उद्योगों हेतु सामान्य सुविधाएँ; उद्योगों से संबंध भूमि एवं उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि; अनुमोदित एवं लंबित परियोजनाओं; राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन एवं वदियुत संबंधी आधारभूत सुविधाओं; केंद्रीय/राज्य सरकारी प्रोत्साहन एवं नविश/रोज़गार आधारित लक्ष्यों इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को सम्मलित किया गया है।

### डेटाबेस में नहिति सूचनाएँ

- उल्लेखनीय है कि इस डेटाबेस के अंतर्गत प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र/समूह से हवाईअड्डे/बंदरगाह की दूरी के संबंध में न केवल समस्त जानकारी बलकित्स क्षेत्र वशिष का उपग्रह आधारित मानचित्र भी उपलब्ध है।
- इसके अतिरिक्त कृषिगत फसलों उदाहरण के तौर पर - फाइबर फसलें, अनाज, तिलहन, वृक्षारोपण फसलें, दलहन एवं मसालों सहित बागवानी फसलों के संबंध में भी डेटा उपलब्ध है।

### नोडल नकिया

- इस डेटाबेस को औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन वभिग (Department of Industrial Policy and Promotion - DIPP) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वभिग (National e-Governance Division) के साथ-साथ बी.आई.एस.ए.जी (गुजरात सरकार के तहत अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना वजिज्ञान संस्थान) द्वारा वकिसति किया गया है।

इस प्रोजेक्ट की सफलता/असफलता इस बात पर नरिभर करती है कि इसके अंतर्गत राज्य सरकारों की कतिनी सक्रियि भागीदारी है। वर्तमान में, इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे अधिक सक्रियि राज्य महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश है। कुछ सीमा तक उड़ीसा, कर्नाटक एवं तमलिनाडु भी इसके अंतर्गत नरितर अपना योगदान बढा रहे है। यही कारण है कि बहुत जलद केंद्र सरकार द्वारा कुछ अन्य राज्य सरकारों के साथ मलिकर इस संबंध में कार्यशालाओं का आयोजन करने की भी योजना है ताकि वनिर्माण क्षेत्र में अधिक से अधिक नविश को आकर्षित करने एवं रोज़गार के अवसरों में बढोतरी करने के संबंध में डेटाबेस की महत्ता को स्पष्ट किया जा सके।

